R.N.I. No. UPHIN/2023/86842 वर्ष : 02 अंक : 151 | लखीमपुर–खीरी, शनिवार 19 अक्टूबर 2024 | पृष्ठ – 04 मूल्य – 01

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

संज्ञान दृष्टि

एक सम्पूर्ण अखबार

मोबाइल नं0–7080049049 | sangyandristinewspaper@gmail.com | website-Sangyannews.com | twitter-Sangyannews

लखीमपुर–खीरी, दिल्ली एनसीआर के साथ–साथ इंदौर, गौरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बहराइच, लखनऊ, अयोध्या, गया (बिहार)

एक नज़र

लखनऊ– श्रीराम औद्योगिक अनाथालय से 9 लड़कियां भागीं, 2 लड़कियों को पुलिस ने बरामद किया, 7 की तलाश, सुबह के समय पुलिस को अनाथालय से सूचना मिली, अलीगंज में श्रीराम औद्योगिक अनाथालय का मामला।

लखनऊ– मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ की जीरो टॉलरेंस नीति, साढ़े सात साल में 80 हजार से अधिक अपराधियों को सजा, 54 अपराधियों को सुनाई गई मृत्युदंड की सजा, महिला, किशोरियों के खिलाफ अपराधों में सर्वाधिक मृत्युदंड, किशोरियों से संबंधित केस में 28,700 अपराधियों को सजा, प्रदेश के 69 माफिया, गिरोह के 29 अपराधियों को सजा, टॉप 10 कैटेगरी के 496 अपराधियों को दिलाई गई सजा।

देवरिया– डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक देवरिया पहुंचे, रविंद्र किशोर शाही के प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, समाज वादी के डीएनए में अराजकता–ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे– ब्रजेश, 'जो भी कानून तोड़ेगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे।

कुशीनगर– बेरोजगार युवकों के लिए आईपीएल इंटर्नशिप, इंटर्नशिप में प्रशिक्षित बच्चे करेंगे किसानों की मदद, इंटर्नशिप कर चुके बच्चे भविष्य में बन सकेंगे अच्छे किसान, आईपीएल की इस पहल से बेरोजगार बच्चे भी होंगे प्रोत्साहित, कुल 53 बच्चों ने आईपीएल इंटर्नशिप प्रोग्राम में लिया भाग, प्रशिक्षण के दौरान 6 हजार रुपए टोकन मनी देकर मदद, आईपीएल खड्डा 53 बच्चों के साथ शुरू किया कार्यक्रम।

बदायूं– बदायूं में नहीं लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे का परिवार, योगेश कुमार के मां बाप की हो चुकी है मौत, परिवार के नाम पर एक भाई, दो बहनें हैं, 1 बहन की हो चुकी शादी, दूसरी रहती बुआ के पास, पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ था योगेश कुमार, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर है योगेश, मीडिया से बातचीत में खुद को गिरफ्तार बता रहा था।

आरबीआई पुलिस नहींय यह वित्तीय बाजार पर निगरानी रखता है और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई करता है', बोले गवर्नर

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (त्ठप्) पुलिस की तरह काम नहीं करता है, बल्कि वह वित्तीय बाजार पर कड़ी निगरानी रखता है और जब भी जरूरी होता है, नियामकीय कार्रवाई करता है। त्ठप् के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम में यह बात कही। केंद्रीय बैंक की ओर से सचिन बंसल की नवी फिनसर्व और तीन अन्य एनबीएफसी को 21 अक्टूबर की कारोबार समाप्ति से ऋण स्वीकृत करने और वितरित करने से रोकने के निर्देश देने के एक दिन बाद, गवर्नर ने यह टिप्पणी की।

ब्लूमबर्ग की ओर से आयोजित इंडिया क्रेडिट फोरम में दास ने कहा, ''नहीं... हम पुलिसकर्मी नहीं हैं। हम वित्तीय बाजार की निगरानी करते हैं। हम बहुत बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। हम ऋण बाजारों पर निगरानी रखते हैं और...जब जरूरी हो जाता है, हम कार्रवाई करते हैं।''

आरबीआई गवर्नर दास ने कहा कि यह भारत का समय है, भारत की विकास गाथा अक्षुण्ण है। मुद्रास्फीति अब लक्ष्य सीमा के काफी भीतर आ गई है। इसके और कम होने की उम्मीद है।उन्होंने कहा कि वास्तव में इसमें महत्वपूर्ण जोखिम हैं, और आरबीआई विकास और मुद्रास्फीति दोनों के संबंध में समग्र दृष्टिकोण की निगरानी करने के प्रति बहुत सावधान है।

ब्याज दरों में कटौती फिलहाल जोखिम भरा होगा–ब्याज दरों में कटौती की संभावना पर आरबीआई गवर्नर ने कहा कि ऐसा करना बहुत ही अपरिपक्व और बहुत बहुत जोखिम भरा होगा। खुदरा महंगाई अब भी बहुत अधिक है और भविष्य की मौद्रिक नीति आय के आंकड़े और बाजार के आउटलुक पर निर्भर रहेगी। इसी महीने मौद्रिक नीति समिति ने अपनी तीन दिवसीय बैठक के बाद नीतिगत ब्याज दरों को स्थिर रखने का फैसला किया था। हर दो महीने पर के अंतराल पर होने वाली मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक दिसंबर में होगी। इसके फैसले का एलान गवर्नर 06 दिसंबर को करेंगे।

अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के बाद आखिर सत्येंद्र जैन का भी नंबर आ ही गया, 18 महीने बाद आएंगे जेल से बाहर

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) नेता और दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येन्द्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी। जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 30 मई, 2022 को कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से धन शोधन के आरोप में गिरफ्तार किया था। विशेष न्यायाधीश विशाल गोग्ने ने कहा कि मुकदमे में देरी और 18 महीने की लंबी कैद और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सुनवाई शुरू होने में काफी समय लगेगा, निष्कर्ष निकालना तो दूर, आरोपी राहत के लिए अनुकूल रूप से उपयुक्त है। आप नेता को जमानत देते हुए अदालत ने कहा कि वह मामले में गवाहों से संपर्क नहीं करेंगे और मुकदमे को प्रभावित नहीं करेंगे। वह भारत से बाहर यात्रा भी नहीं करेंगे। न्यायाधीश ने 50,000 रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि की दो जमानत राशि पर राहत दी। जैन को प्रवर्तन निदेशालय ने 30 मई, 2022 को कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की शिकायत पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सत्येन्द्र जैन ने 14 फरवरी, 2015 से 31 मई, 2017 तक विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर चल संपत्तियां अर्जित की थीं, जिसका वह संतोषजनक हिसाब नहीं दे सके।

सीएम योगी बोले यूपी में असीमित क्षमता, पूरा होगा वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का सपना

उ0प्र0। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश को एक ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने के संकल्प की पूर्ति की दिशा में जारी प्रयासों, अब तक के परिणामों और भावी नीति पर विमर्श किया। बैठक में विभिन्न मंत्रीगणों, शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों, सलाहकारों, विशेषज्ञों की उपस्थिति रही। बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी 10 सेक्टरों में जारी कार्यों की समीक्षा की। कंसल्टिंग एजेंसी डेलॉयट इंडिया ने विस्तार से प्रदेश के आर्थिक परिवेश की वर्तमान स्थिति और संभावित भावी परिणाम, उद्योग जगत की अपेक्षाओं आदि के संबंध में सेक्टरवार विस्तार से जानकारी दी।

बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विगत 07 वर्षों के नियोजित प्रयासों से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आज सार्वकालिक सर्वश्रेष्ठ स्थिति में है। 2021–22 में प्रदेश की कुल जीडीपी घ्16.45 लाख करोड़ थी जो आज 2023–24 में घ्25.48 लाख करोड़ से अधिक हो गई है। इस वर्ष हमारा जीएसडीपी लक्ष्य घ्32 लाख करोड़ का है। सभी के सहयोग से यह लक्ष्य भी पूरा होगा। इन 07 वर्षों में जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक हुई है। उत्तर प्रदेश आज देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देश के विकास का ग्रोथ इंजन बन रहा है। सेक्टरवार विकास के हमारे प्रयासों के आशातीत परिणाम मिल रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए अलग–अलग सेक्टरों के लिए सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) का जो लक्ष्य रखा गया, उसके सापेक्ष अधिक वृद्धि देखी गई है। कृषि और सहायक सेक्टर के लिए अनुमानित जीवीए 5.85 लाख करोड़ के सापेक्ष 5.98 लाख करोड़, विनिर्माण के 2.48 लाख करोड़ के सापेक्ष 2.79 लाख करोड़, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और कम्युनिकेशन के अनुमानित जीवीए के सापेक्ष 129: की वृद्धि दर्ज की गई है। स्पष्ट है व्यापार, होटल, परिवहन और प्रसारण से संबंधित संचार सेवाओं की वृद्धि दर में तेजी आई है। ऐसे ही हाल अन्य सेक्टरों में भी है। ओवरऑल 2023–24 में राज्य के लिए अनुमानित जीएसवीए 23 लाख करोड़ के सापेक्ष सकल मूल्य वर्धन 23.24 लाख करोड़ रहा है। यह स्थिति अर्थव्यवस्था की बेहतर स्थिति को प्रदर्शित करती है।

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तेज वृद्धि दर उत्साहित करने वाली है–मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रान्सफार्म के मंत्र का अर्थव्यवस्था के द्वितीयक खंड सबसे अच्छा परिणाम देखने को मिला है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तेज वृद्धि दर उत्साहित करने वाली है। भविष्य की जरूरतों के दृष्टिगत लैंडबैंक के विस्तार, नीतिगत सुधार और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अपने प्रयासों को तेज करना होगा। अनेक निवेशक उत्तर प्रदेश में आने के लिए तैयार हैं। टेक्सटाइल पार्क, सोलर पार्क, प्लेज पार्क के अनेक प्रस्ताव मिल रहे हैं। हमें इस अनुकूल अवसर का लाभ उठाना चाहिए।

जल्द ही जाई जाएगी आईटी से जुड़ी पॉलिसी–मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आईटी सेक्टर को उद्योग का दर्जा दिया गया है। गौतमबुद्ध नगर आज आईटीध्आईटीईइस का ग्लोबल हब बन कर उभरा है। प्रदेश में आईटीध्आईटीईएस टेस्टिंग सेंटर की स्थापना का प्रयास करें। लखनऊ में एआई सिटी की भूमि चिन्हित की जा चुकी है, इससे संबंधित पॉलिसी यथाशीघ्र लाई जाए। परियोजना पर काम तेज किया जाना चाहिए। हमें ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेनिंग के लिए भी प्रस्ताव मिले हैं, इसकी बेहतर संभावनाओं का लाभ लेने के लिए हमें यथाशीघ्र अपनी ड्रोन पॉलिसी लागू करनी चाहिए। स्टार्ट अप पंजीकरण के लिए कानपुर के साथ–साथ नोएडा में भी सुविधा कार्यालय प्रारंभ कराया जाए। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के लिए नगर निकायों व ग्राम पंचायतों का आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। इनके आय संवर्धन के लिए ठोस कार्ययोजना बनाई जाए। गांव हो या कस्बे, हर जगह आम आदमी को अच्छी सड़क, शुद्ध पेयजल, बेहतर जनसुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। आकांक्षात्मक जनपद और आकांक्षात्मक विकासखंड की प्रगति की लगातार समीक्षा की जाए, जहां कमी हो, उसे दूर किया जाए।

बेनामी संपत्ति लेनदेन पर रोक लगाने वाले प्रावधानों पर 'सुप्रीम' निर्णय, उच्चतम न्यायालय ने वापस लिया फैसला

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को अपने 2022 के उस फैसले को वापस ले लिया, जिसमें बेनामी संपत्ति लेनदेन पर रोक लगाने वाले कानून के दो प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किया गया था। ये प्रावधान ऐसे सौदों और संपत्तियों को अधिकारियों की तरफ से कुर्क किए जाने पर रोक लगाते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के फैसले को लिया वापस–सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने 23 अगस्त, 2022 के फैसले पर केंद्र की समीक्षा याचिका की सुनवाई करते हुए पूर्व सीजेआई एन.वी. रमण की अध्यक्षता वाली तीन–सदस्यीय पीठ की तरफ से दिए गए फैसले को वापस ले लिया।

2022 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया था फैसला–शीर्ष अदालत ने अगस्त 2022 के अपने फैसले में तब माना था कि बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 की धाराएं 3(2) और पांच 'स्पष्ट रूप से मनमानी' होने के कारण असंवैधानिक थीं। अधिनियम की धारा–तीन बेनामी (किसी व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति के माध्यम से रखी गई संपत्ति) लेन–देन पर रोक से संबंधित है, जबकि धारा–पांच कुर्क करने योग्य बेनामी संपत्ति से संबंधित है। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों से सहमति जताई कि इन दोनों प्रावधानों की वैधता को तत्कालीन पीठ के समक्ष चुनौती नहीं दी गई थी।

उच्चतम न्यायालय ने समीक्षा याचिका को दी अनुमति–पीठ ने कहा, इस मामले को देखते हुए, समीक्षा की अनुमति दी जानी चाहिए। यह एक सामान्य कानून है कि किसी वैधानिक प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने पर पक्षों के बीच जीवंत सुनवाई और विवाद की अनुपस्थिति में निर्णय नहीं लिया जा सकता है। इसके नतीजन उच्चतम न्यायालय ने समीक्षा याचिका को अनुमति दे दी। अगस्त 2022 के अपने फैसले में, उच्चतम न्यायालय ने माना था कि अधिकारी बेनामी संपत्ति कानून के लागू होने से पहले किए गए लेनदेन के लिए आपराधिक मुकदमा या जब्ती की कार्यवाही शुरू या जारी नहीं रख सकते।

हिंदी से इतनी नफरत क्यों? तमिलनाडु के सीएम ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, लोकल लैंग्वेज मंथ को भी जोर–शोर से मनाया जाना चाहिए

तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर गैर–हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी भाषा–उन्मुख कार्यक्रम आयोजित करने की केंद्र सरकार की योजना पर पुनर्विचार करने की वकालत की है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि इस तरह की पहल अलग–अलग भाषाई पहचान वाले क्षेत्रों के बीच संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। अपने पत्र में स्टालिन ने भारत की भाषाई विविधता को स्वीकार करने और उसका जश्न मनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि जैसा कि आप जानते हैं, भारत का संविधान किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं देता है। हिंदी और अंग्रेजी का उपयोग केवल कानून जैसे आधिकारिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

स्टालिन ने आगे उन राज्यों में हिंदी को बढ़ावा देने के खिलाफ तर्क दिया जहां यह व्यापक रूप से नहीं बोली जाती है। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में, भारत जैसे बहुभाषी देश में हिंदी को विशेष स्थान देना और गैर–हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी माह मनाना अन्य भाषाओं को कमतर करने के प्रयास के रूप में देखा जाता है। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि यदि केंद्र सरकार ऐसे हिंदी भाषा के आयोजनों पर जोर देती है, तो उसे प्रत्येक राज्य में समान गर्मजोशी के साथ स्थानीय भाषा समारोहों को भी बढ़ावा देना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने सुझाव दिया कि भारत सरकार विभिन्न राज्यों में मान्यता प्राप्त सभी शास्त्रीय भाषाओं की समृद्धि का सम्मान करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित कर सकती है, उन्होंने कहा, ''इससे सभी के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बढ़ सकते हैं।

स्टालिन की अपील भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य में समावेशिता के महत्व को रेखांकित करती है और इसका उद्देश्य क्षेत्रीय पहचान का सम्मान करते हुए एकता की भावना को बढ़ावा देना है। यह पत्र एक विविध राष्ट्र में भाषा और पहचान के बारे में चल रही चर्चा को दर्शाता है।

मनरेगा कार्यों की ड्रोन तकनीक से हो रही निगरानी

सीतापुर, हरदोई और शाहजहांपुर पहुंची ड्रोन टीम

सीतापुर, हरदोई और शाहजहांपुर में मनरेगा कार्यों की ड्रोन कैमरे से परखी जाएगी जमीनी हकीकत

सीतापुर, हरदोई और शाहजहांपुर की 20–20 ग्राम पंचायतों में हुये कार्यो का ड्रोन से होगी निगरानी

वित्तीय वर्ष 2023–24 में किये गये कार्यों की हकीकत देखेगी टीम

मनरेगा योजनांतर्गत किये गये कार्यों को परखेगी ड्रोन टीम

गौरव यादव

लखनऊ (संज्ञान दृष्टि)। प्रदेश में मनरेगा योजनांतर्गत किये गये कार्यों की ड्रोन तकनीकी से निरंतर निगरानी और निरीक्षण का कार्य किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य के कुशल निर्देशन में ग्राम्य विकास विभाग लगातार तकनीक पर जोर दे रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा तकनीकी का इस्तेमाल हो व आम नागरिक जागरूक हो इसको लेकर लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।

उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व व निर्देशन में ग्राम्य विकास विभाग की ग्रामोन्मुखी योजनाओं का क्रियान्वयन जहां बेहतर तरीके से किया जा रहा है, वहीं योजनाओं को अमलीजामा पहनाने में कहीं घालमेल न होने पाये ,इसके लिए सतत् रूप से निगरानी किये जाने की व्यवस्था की गयी है। मनरेगा योजनांतर्गत कार्यों की गुणवत्ता पर प्रभावी व पैनी नजर रखने के भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। मनरेगा कार्यों की ड्रोन तकनीक से वीडियोग्राफीध् फोटोग्राफी कर निगरानी का कार्य निरंतर जारी है। राज्य मुख्यालय स्तर पर तैनात टीमों द्वारा जनपदों में जाकर कार्यों की निरंतर ड्रोन तकनीक से वीडियोग्राफीध् फोटोग्राफी का कार्य किया जा रहा है, इसी क्रम में अब टीम सीतापुर, हरदोई और शाहजहांपुर जनपद में पहुंची टीम भ्रमण कर योजनांतर्गत किये गये कार्यों को परखेगी।

मनरेगा योजना के अन्तर्गत कार्यस्थलों पर निगरानी ड्रोन प्रणाली के माध्यम से भी की जा रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशो के क्रम में राज्य मनरेगा मुख्यालय पर ड्रोन टीम तैनात की गयी थी। राज्य स्तरीय ड्रोन टीम का उपयोग मनरेगा कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षणधनिगरानी के लिये किया जा रहा है। आयुक्त, ग्राम्य विकास श्री जी0एस0 प्रियदर्शी द्वारा सीतापुर, हरदोई और शाहजहांपुर जनपद की चिन्हित की गईं 20–20 ग्राम पंचायत में वर्ष 2023–24 में मनरेगा के अन्तर्गत करायें गये कार्यों की ड्रोन टीम से वीडियोग्राफीध् फोटोग्राफी कर निरीक्षण धनिगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। इस सम्बन्ध में सीतापुर, हरदोई और शाहजहांपुर जनपद के मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि वह ड्रोन टीम को सहयोग प्रदान करने हेतु अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटी लगाना सुनिश्चित करें। बता दें कि निर्धारित रोस्टर के अनुसार सीतापुर, हरदोई और शाहजहांपुर जनपद के अलग–अलग विकास खण्डों की 20–20 ग्राम पंचायतों में निर्धारित रोस्टर के अनुसार ड्रोन टीम सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन कर कर रही हैं।

सम्पादकीय

प्रतीकों में उलझी न्यायपालिका

कन्नलेजियम प्रणाली के खिलाफ कानून मंत्री, न्यायपालिका के लिए अशुभ संकेतक्या यह न्यायपालिका के खिलाफ युद्घ का एलान है?

प्रतीकों के खेल में अब तक इस देश की राजनीति ही उलझी हुई थी, अफसोस है कि अब न्यायपालिका भी इसका हिस्सा बन गई है। न्याय की देवी की मूर्ति में जो फेरबदल किए गए और इसके पीछे जो तर्क दिए गए, वो इस बात का प्रमाण हैं कि न्याय व्यवस्था को त्रुटिहीन और पूरी तरह से दुरुस्त करने की कोशिश की जगह भावनात्मक बातों को अधिक महत्व दिया जा रहा है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की लाइब्रेरी में न्याय की देवी की नयी मूर्ति लगायी गयी है। देश के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के आदेश पर नयी मूर्ति बनी है, जिसमें पुरानी मूर्ति से अलग वेशभूषा और प्रतीक बने हैं। सफेद रंग की मूर्ति में आंखों से पती हटा दी गई है, उसका परिधान भारतीय कर दिया गया है और हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब दी गई है। कहा जा रहा है कि इस बदलाव से यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि कानून अंधा नहीं होता। तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में लिखा है जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अर्थात हम अपनी भावनाओं और नजरिए के अनुरूप ही चीजों को देखते और परखते हैं। आंख पर पती होने को अंधत्व से भी जोड़ा जा सकता है और निष्पक्षता से भी। 1983 से में अमिताभ बच्चन, रजनीकांत और हेमा मालिनी की फिल्म आई थी अंधा कानून।

जिसमें दिखाया गया है कि अमिताभ बच्चन याने नायक को एक ऐसे जुर्म की सजा होती है, जो उसने किया ही नहीं, उसके परिवार को भी अत्याचार का शिकार बनाया जाता है और उसके बाद फिल्म में बार–बार ये अंधा कानून है, गीत पार्श्व में बजता रहता है और न्याय देवी की मूर्ति भी दिखाई जाती है, जिसकी आंखों पर पती बंधी है। कानून के अंधे होने की धारणा को फिल्म के जरिए समाज में और मजबूत किया गया। और अब करीब 4 दशक बाद एक प्रचलित धारणा के अनुरूप फैसला लिया गया है। समझा जा सकता है कि देश में हाल के वर्षों में हुए कई बदलावों के पीछे कई बरसों की कोशिश रही है। नेहरू संग्रहालय को पीएम म्यूजियम में बदलना, इंडिया गेट पर नेता जी की मूर्ति, जम्मू– कश्मीर से 370 की वापसी, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, संसद में सेंगोल की स्थापना या इंडियन पीनल कोड, आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस का लागू होना, ऐसे ही फैसलों की चंद मिसाल हैं। अभी आने वाले वर्षों में अगर हम भारतीय मुद्रा पर गांधीजी की जगह किसी और की तस्वीर देखें तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बहरहाल, अब तक न्याय की जो मूर्ति देश में हुआ करती थी, वो यूनानी देवी जस्टिया की तरह होती थीं, जिनके नाम पर ही जस्टिस यानी न्याय शब्द बना है। इस मूर्ति की आंखों पर पती का मतलब था कि कानून किसी का ओहदा, धर्म, जाति न देखकर सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है। वहीं अभी जिस तलवार को हिंसा का प्रतीक बताकर हटाया गया है, दरअसल उसके जरिए यह संप्रेषित किया गया था कि कानून के पास ताकत है और वो गलत करने वालों को सजा दे सकता है। पुरानी मूर्ति में तराजू भी देवी के एक हाथ में होता था, वो नयी मूर्ति में बरकरार रखा गया है। जो यह दिखाता है कि अदालत में कोई भी फैसला तर्क की तुला पर ही किया जाएगा। नयी मूर्ति में तराजू अब भी रखा गया है, यह गनीमत है, वर्ना इसे भी किसी आधुनिक डिवाइस से बदला जा सकता था कि तराजू की जगह तौलने–मापने के आधुनिक साधन हमारे पास उपलब्ध हैं। बहरहाल, तलवार को हिंसा का प्रतीक जब मान ही लिया गया है तो फिर विश्वविद्यालय परिसरों में तोपें रखने के औचित्य पर भी विमर्श होना चाहिए। क्या तोप, तलवार से अधिक घातक नहीं होती है। और तलवार हटाकर संविधान रखने के फैसले में राजनीति की छाप नजर आती है। हाल में संपन्न लोकसभा चुनावों के दौरान संविधान बचाने का मुफ्रा राजनीति के कें८ में आ गया और तब से अब यह गर्माया हुआ है। भाजपानीत एनडीए सरकार ने संविधानहत्या विरोधी दिवस मनाने का ऐलान भी कर दिया है।

वहीं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन अब भी जनता को यही बता रहे हैं कि भाजपा के शासन में संविधान को खतरा बरकरार रहेगा। संविधान की रक्षा और सम्मान का विमर्श सियासी गलियारों से उठकर न्यायालय के दरवाजे तक पहुंच जाएगा, यह अनुमान शायद ही किसी ने लगाया हो। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, इन तीनों अंगों के जरिए ही संविधान के पालन की सुचारू व्यवस्था बनाई गई थी। फिर न्यायपालिका में इसके अलग से महिमामंडन की कोई आवश्यकता नहीं थी। बल्कि जरूरत इस बात की थी कि अदालतें संविधान के मुताबिक फैसले तो लें ही, साथ ही कोई इसका उल्लंघन करते दिखे तो स्वतरू संज्ञान लेकर गलत को सही भी करें।जैसे संविधान में धर्मनिरपेक्षता की जो व्यवस्था है, उसके मुताबिक सा्ता या प्रशासन में बैठे किसी भी व्यदि को सार्वजनिक तौर पर धार्मिक कार्यममों में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि अब पुलिस की वर्दी पहने लोग हवन में बैठते हैं, कांवड़ यात्रा पर फूल बरसाते हैं, संसद के भीतर मंत्रोच्चार होता है और प्रधानमंत्री जजमान की भूमिका में दिखते हैं। क्या अब न्याय की देवी के हाथों का संविधान आने के बाद देश में ऐसी घटनाओं का दोहराव रुकेगा। क्या सा्ता हासिल करने के लिए जिस किस्म के गैरकानूनी तरीके आजमाए गए हैं, उन पर रोक लगेगी। क्या उमर खालिद जैसे लोग जो बिना जुर्म साबित हुए जेलों में बंद हैं और जमानत भी जिन्हें नहीं दी जाती, उनके साथ इंसाफ होगा। क्या खुली आंखों वाली न्याय की देवी कपड़ों से पहचान की बात को अस्वीकार करेंगी। वैसे न्याय की मूर्ति में तब्दीली आने के साथ ही एक खबर आई है, कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि मस्जिद में भगवान राम की प्रशंसा में नारे लगाने में कुछ गलत नहीं है। देश किस तरफ बढ़ चुका है, यह अब साफ नजर आ रहा है।

स्वागत लाथार्थी के तौर पर नागरिक

सूबाई चुनावों का ऐलान हो चुका है, महाराष्ट्र और झारखंड में अगले माह के अंत तक नई सरकार का गठन होगा। वैसे इस ऐलान के ऐन पहले एक कर्तव्यनिष्ठ पत्रकार द्वारा महाराष्ट्र सरकार को भेजी लीगल नोटिस चर्चा का विषय बनी रही। इस नोटिस का फोकस महाराष्ट्र सरकार द्वारा आनन–फानन हाल में शुरू की गयी श्लाडकी बहिण योजना से है, जिसके तहत महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रूपए दिए जाएंगे। याद रहे लोकसभा चुनाव में जब महाराष्ट्र में भाजपा की अगुआई वाले गठबंधन को विपक्षी इंडिया गठबंध्न की तुलना में कम सीटें मिलीं,तब इस योजना को शुरू किया गया। नोटिस में कहा गया है कि सरकार का यह दावा कि इतनी मासिक सहायता महिलाओं के लिए काफी होगी, तथ्यों से परे है, इतना ही नहीं ऐसी खैरात निर्भरता की संसैति को बढ़ावा देती है और वह कल्याणकारी राज्य के समूचे विचार को खत्म कर देती है। इस खास मामले में सरकार का जवाब जो भी हो, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि इस लीगल नोटिस ने बेहद जरूरी सवाल उठाए हैं। इसमें कहा गया है कि इस योजना के लिए सरकार ने प्रति साल 46,000 करोड़ रुपए के खर्चे का अनुमान लगाया है और इसे पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया से तीन हजार करोड़ रुपए का कर्जा भी ले लिया है। उनके मुताबिक यह योजना राज्य की वि्ीय स्थिति को और नाजुक कर देगा तथा उसका राजकोषीय घाटा तीन फीसदी से लेकर 4,6 फीसदी तक पहुंच जाएगा।

वि्ीय तथा अन्य मामलों के अलावा इस नोटिस ने अन्य सवाल उठाए हैं, मसलन महिलाओं के लिए बनी इस योजना से ट्रांसजेंडर महिलाओं को बाहर रखा गया है और सबसे अहम बात यह है कि यह योजना राज्य और स्त्रियों के बीच के रिश्ते को भाई–बहन के गतिविज्ञान में देखता है, जो संविधान निर्माताओं द्वारा नजरिये को उलट देता है, जो इसे राज्य और नागरिक के बीच के सम्बन्ध के तौर पर देखता है। इस हस्तक्षेप को लेकर यह प्रतिमिया सबसे पहले सुनने को मिल सकती है कि इस योजना में अनोखा कुछ नहीं है। मध्य–देश में शुरू की गयी लाड़ली बहिना योजना की बात की जा सकती है जिसे शिवराज सिंह चौहान की पूर्व सरकार ने शुरू किया था और बाद में कहा गया था कि भाजपा को लोकसभा चुनावों में जो जीत मिली इसके पीछे इसी योजना का हाथ रहा है जिसके तहत भी महिलाओं को हर माह कुछ निश्चित रकम दी जाती है। मुमकिन है केन्द्र सरकार द्वारा 80 करोड़ भारतीयों के लिए हर माह पांच किलो अनाज देने की बात भी कोई कर सकता है जो आने वाले पांच साल तक चलेगी, उसका भी इसके तहत उल्लेख हो।ऐसी योजनाओं की प्रचुरता का– जिनमें से कई योजनाएं विपक्षी पार्टी की सरकारों ने भी शुरू की हैं मतलब यह क़ाई नहीं है कि हम उन सवालों को सामने न रखें, जो पहले से उठे न हों।

दरअसल इससे जुड़े अन्य मामलों के चलते उसकी अहमियत बढ़ गयी है बिना किसी पूर्वयोजना के चुनावों के ऐन पहले शुरू की गयी इस योजना का मतलब यह भी है कि इससे सरकार की पहले से चली आ रही योजनाओं पर भी गहरा असर पड़ेगा। पहले से जिन हाशियौत तबकों को सबसिडी दी जाती रही है, उसमें कटौती होगी या विलंब होगा। मालूम हो कि इस बात को सरकार के आलोचक नहीं बल्कि खुद केन्द्र सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी ने उठाया है। राज्य की पहले से चली आ रही नाजुक वि्ीय स्थिति का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि–जब राज्य पहले से ही कर्जे में डूबा है तो ऐसी योजना की व्यावहारिकता प्रश्नों के घेरे में है। अगर हम घटनामम की तरफ गौर से देखें तो यह साफ है कि राज्य ने नागरिकों के अपने हित से जुड़े मामले में निर्णय प्रमिया में उनकी सहभागिता से पूरी तरह इन्कार किया है। दूसरे, जल्दबाजी में शुरू की गयी यह योजना एक तरह से नागरिकों की श्बौद्धिक क्षमताश को भी कम आंकती है और लोगों में आपस में ही संदेह और अविश्वास पैदा करती है। इसका मतलब और कुछ नहीं बल्कि नागरिक और जनतंत्र के बीच जो एक खास किस्म का रिश्ता बना हुआ है जहां नागरिक अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं, उन्हें अभिव्यदि की स्वतंत्रता आदि अधिकार हासिल होते है और राज्य का कर्तव्य होता है कि वह उन्हें पूरी करे। को एक तरह से भंग कर देना या तोड़ देना। शायद हुक्मरानों को यह लगता हो कि ऐसा रिश्ता अब पुराना हो गया है और उन्हें लगता हो कि पुराने दिन ही लौटाए जा सकें, जहां जनता प्रजा के तौर पर उपस्थित होती थी, जो शहंशाहों और राजे–रजवाड़ों की ँपासष्टि पर निर्भर होती थी।

हम हाल के वर्षो में उन घटनाओं को याद कर सकते हैं कि किस तरह देश की वि्ामंत्री ने एक सार्वजनिक वितरण योजना की दुकान पर दुकानदार को इसलिए डांटा कि उसने प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर नहीं लगाई थी या खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ही एक जनसभा में किस तरह ऐसी सहायता को लेकर जनता क्या सोचती है, इसका किस्सा बयान किया था। इस तरह आज हम यही देख रहे हैं कि गणतंत्र के 75 वे वर्ष में एक आम नागरिक जो अधिकार सम्पन्न व्यदि है, उसे राज्य की दया पर छोड़ा जा रहा है। यह एक किस्म के नए रिश्ते को स्थापित करना है जहां नागरिक के बजाय वह एक लाभार्थी के तौर पर उपस्थित रहे। 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही विश्लेषकों ने इस किस्म की संभावना प्रकट की थी। अपने पहले ही भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया था कि उनकी सरकार गुड गवर्नेंस का सूत्रपात करेगी, जिसका सूत्र वाक्य होगा कि श्न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासनध्गवर्नसश. यह एक बाहर से आकर्षित करने वाला विचार था, लेकिन उसकी वास्तविकता लोगों के सामने तभी स्पष्ट की गयी थीं।

विश्लेषकों ने बताया था कि उसका मतलब है कल्याणकारी खर्चोंश में कटौती या कम से कम इस बात को स्थापित करना कि आर्थिक तौर पर वह एक गलत विचार है। इसके तहत चुने हुए राजनीतिक प्रति निधियों के बजाय नीति निर्माण में बिना चुने गए विशेषज्ञों को वरीयता देने की बात थी। जहां पारदर्शिता, जवाबदेही, सशदिकरण या नागरिक सहभागिता जैसी बातों को इस गुड गवर्नेंस के एजेण्डा में शामिल किया गया था, लेकिन उनके सामने कोई सामाजिक रूपांतरण का संदर्भ नहीं था बल्कि वह गुड गवर्नेंस के नवउदारवादी विजन का ही हिस्सा था। सशदिकरण का भी यहां अलग मतलब था, यहां उसका अर्थ था टेक्नालन्नजी या ई–गवर्नस के जरिए हाशिये के लोगों को ताकत प्रदान करना।

अपने आलेख का अंत अग्रणी विश्लेषक और हिन्दू के संपादक मंडल के सदस्य जी सम्पथ ने यह कहते हुए किया था कि गुड गवर्नेंस का मतलब होगा राजनीति जो एक तरह से जनतंत्र की आत्मा होती है उसे प्रबंधन से प्रतिस्थापित करना और अधिकारों के बिना नागरिकता को बढ़ावा देना। हाल के समयों में विद्वानों और विश्लेषकों ने इस बात को साफ किया है कि किस तरह ऐसी योजनाएं एक अधिकार संपन्न नागरिक को प्रजा में या लाभार्थी में बदलती दिखती है या किस तरह यह कल्याणकारिता, सामाजिक नागरिकता को बढ़ावा देना और एकजुटता कायम करना ऐसे तमाम मुदिकामी उफ्रेश्यों से तौबा करती है, और नागरिकों को राज्य के निष्मिय लाभार्थी में तब्दील करती है, जो राज्य की खैरात का इन्तजार करता रहता है, न कि एक अधिकारसंपन्न, अपना हक जताने वाले व्यदि के तौर पर।

जाहिर सी बात है कि कल्याणकारिता के इस मन्नडल की पड़ताल आवश्यक है जिसने एक तरह से वितरण के संघर्ष का ही गैरराजनीतिकरण कर दिया है या जनतंत्र को प्रभावित किया है जहां हमारे सामने अधिकार संपन्न नागरिक नहीं, खैरात के इन्तजार में खड़े लाभार्थी हैं। तय बात है संविधान निर्माताओं ने यह बात सपने में नहीं सोची होगी कि गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ नागरिकों के नयी प्रजा के तौर पर या लाभार्थी के तौर पर उपस्थित होने में ही खर्च होगी।

पाक में जयशंकर

भले ही इस्लामाबाद में भारत–पाकिस्तान की द्विपक्षीय वार्ता नहीं थी, लेकिन लगभग नौ साल बाद किसी भारतीय विदेश मंत्री की पहली पाकिस्तान यात्रा के गहरे निहितार्थ हैं। नई दिल्ली द्वारा इस यात्रा को हरी झंडी देना ही इस बात का प्रबल संकेत है कि पर्दे के पीछे से की जा रही कूटनीति सार्थक रही है। दरअसल, शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में भाग लेने के लिये विदेश मंत्री के इस्लामाबाद जाने के निर्णय ने कई उम्मीदें जगायी हैं। एससीओ सम्मेलन में भाग लेने जाने से पहले एस जयशंकर ने घोषणा की थी कि पाकिस्तान को लेकर भारत की विदेश नीति निष्मिय नीति नहीं है। निश्चित रूप से भारत सरकार की ओर से यह संकेत देने का प्रयास किया गया कि दिल्ली किसी भी सकारात्मक संकेत का जवाब देने के लिये पूरी तरह से तैयार है। ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान की राजधानी में एससीओ सम्मेलन में एस जयशंकर अपनी दो टूक बात करने से चूके हों। उन्होंने इस्लामाबाद को साफ–साफ शब्दों में इस मंच के जरिये सभ्य तरीके से सुना दिया कि आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद को प्रश्रय देने वाली नीति ही संबंधों में बाधक है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये नीतियां व्यापार गति विधियों, र्जा प्रवाह, कनेक्टिविटी और लोगों से लोगों के संवाद–संबंध बनाने में बाधक बनती हैं। उन्होंने अतीत में एक मंच पर भारत–पाक के बीच पैदा होने वाली परंपरागत कटुता को दरकिनार करते हुए भी कड़े शब्दों में भारत की नीति को जाहिर कर दिया। वहीं दूसरी ओर भले ही शिखर वार्ता की अभी कोई स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर की अपने पाकिस्तानी समकक्ष इशाक डार के साथ अनौपचारिक बातचीत से द्विपक्षीय संबंधों में लंबे समय से उत्पन्न रुकावट खत्म होने की उम्मीद जरूर जगी है। बहरहाल, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि घात और बात की नीति साथ–साथ नहीं चल सकती। जिस ओर एस जयशंकर ने शंघाई सहयोग संगठन मंच का उपयोग करते हुए स्पष्ट इशारा किया भी है।

बहरहाल, इतना तो तय है कि यदि पाक अपनी पुरानी नीतियों को नहीं बदलता तो रिश्तों में जमी बर्फ के पिघलने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। वैसे यह भी हकीकत है कि पाकिस्तान की रीतियों–नीतियों के चलते उससे सीमित जुड़ाव बनाये रखना भारतीय सरकारों के लिये भी एक चुनौती बनी हुई है। इस्लामाबाद, अन्य शब्दों में कहें तो पाकिस्तान सेना मुख्यालय रावलपिंडी की, बार–बार विश्वास को खंडित करने की नीति संबंधों को आगे बढ़ाने के प्रयासों में संदेह को जन्म देती है। यह एक हकीकत है कि आतंकवाद को प्रश्रय देने की पाक की नीति के चलते मेज पर वार्ता न करने के इच्छुक भारत को अपने अविश्वसनीय पड़ोसी के साथ संबंधों के विकल्प तलाशते रहने चाहिए। जिसमें बातचीत का माध्यम खुला रखना भी शामिल हैं। मिकेट डिप्लोमेसी भी अतीत की तरह भारत के लिये मददगार हो सकती है या नहीं, इस पर भी विचार करने की जरूरत है। लेकिन ये प्रयास लंबे समय से दोनों देशों के संबंधों में जमी बर्फ को पिघलाने में मददगार हो सकते हैं। निश्चित तौर पर एस. जयशंकर की पाकिस्तान यात्रा के सार्थक समापन को एक रचनात्मक उपलब्धि के तौर पर तो देखा जा सकता है। भले ही यह एक छोटा कदम हो, लेकिन आगे बढ़ने की दिशा में इस छोटे कदम को भी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि भौगोलिक रूप से पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, जिसे बदला नहीं जा सकता। निश्चित रूप से अब गेंद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के पाले में है कि संबंधों को ईमानदारी से आगे बढ़ाने में वे कितनी शराफत दिखाते हैं। हालांकि, संबंधों को मजबूत करने में उनके भाई और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का ट्रैक रिकॉर्ड विश्वास करने लायक नहीं रहा है। वैसे भी भारत से संबंधों की नई पहल करने से शरीफ को पहले पाकिस्तान सेना से निपटना होगा। जो पर्दे के पीछे से पाकिस्तानी लोकतंत्र को चला रही है। बहरहाल, नई दिल्ली की इसके नतीजे को लेकर उत्सुकता से नजर रहेगी।

आज का राशिफल

मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन

मेष :– अच्छी भावनात्मक अभिव्यदि से संबंधों की मधुरता बढ़ेगी। रोजगार की समस्याओं को लेकर मन चिंतित होगा। किसी बड़ी यात्रा के प्रति मन उत्साहित होगा। असीम प्रतिभाओं के बावजूद असफल होंगे।

वृषभ :– विरोधियों की प्रबलता से कार्यक्षेत्र में कठिनाइयां संभव। जीविका क्षेत्र में नये आयाम उत्साहित करेंगे। कल्पनाओं में जीना छोड़ भौतिक जगत के अनुकूल चलने का प्रयत्न करें।

मिथुन :– किसी सहकर्मी के खराब व्यवहार से कष्ट संभव। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मन दुविधाग्रस्त होगा। पारिवारिक संबंधों में कटुता न आने दें। आवेश में लिये गये निर्णय से पश्चाप संभव।

कर्क :– किसी विपरीतलिंगी संबंध के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। रोजगार में समस्याओं से हतोत्साहित न हों। अपनी क्षमताओं व गुणव्ाा पर भरोसा रखें क्योंकि आगे बहुत सारी सफलताएं मिलने वाली हैं।

सिंह :– कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मन दुविधाग्रस्त होगा। नाजुक संबंधों में भावनात्मक तालमेल बिठाने का प्रयत्न करें। नये कायरें के मियान्वयन हेतु प्रयत्न तीव्र होगा। जीवन साथी से मधुरता कायम रखें।

कन्या :– कोई महत्वपूर्ण आकांक्षा अपनी सार्थकता हेतु उद्वेलित करेगी। दूसरों की आलोचना का असर मनोबल पर कतई न पड़ने दें। ग्रहों की अनुकूलता प्रगति के अच्छे अवसर प्रदान करेगी।

तुला :– कुछ नये उत्साह व कार्य क्षमता की अनुभूति करेंगे। कुछ आर्थिक प्रगति के लिए मन नई–नई युदियों पर केंद्रित होगा। कुछ नई सफलताएं सुखों का आगाज करेंगी। योजनाएं फलीभूत होंगी।

वृश्चिक :– बीती बातों को भूल वर्तमान में जीने का प्रयास करें। रोजगार में अपनी क्षमता का पूर्ण लाभ मिलेगा। बिना वजह दूसरों की पीठ पीछे आलोचना न करें। परिवार में खुशहाल स्थिति से मन प्रसन्न होगा।

धनु :– दूसरों की सफलता से अपने अंदर हीन भावना न पाले। नौकरी का वातावरण थोड़ा अरुचिकर होगा तथा स्थान परिवर्तन का भी योग है। रोजगार में व्यस्तता रहेगी किंतु जरूरी कायरे की पूर्ति समय से करें।

मकर :– रोजगार में कुछ आकस्मिक सफलता मिलने का योग है। पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति में व्यय संभव। प्रयासरत कोई महत्वपूर्ण कार्य हल होने से मन प्रसन्न होगा। कार्यक्षेत्र में क्षमताओं का लाभ उठाएंगे।

कुंभ :– रोजगार क्षेत्र में मिल रहे नये अवसरों का लाभ उठाएंगे। आवेश में लिये गये निर्णय से हानि संभव। राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ेंगी। मित्रवत संबंधों का लाभ प्राप्त होगा। परिवार में खुशहाल माहौल रहेगा।

मीन :– आपकी सारी समस्याएं खुद ब खुद सुलझ जाएंगी। किसी नयी दिशा में सकारात्मक सोच अवश्य रंग लायेगी। पुरानी घटनाओं के स्मरण से मन को कष्ट संभव। जीवन साथी के साथ मधुरता कायम रखें।

खाना खजाना / सेहत / ब्यूटी

यूरिक एसिड के लेवल को कम करने में किसी चमत्कार से कम नहीं हैं, ये 5 ड्राई फ्रूट्स

क्या आप जानते हैं कि मुट्ठी भर सूखे मेवे यूरिक एसिड को नियंत्रित किया जा सकता है? शरीर में अतिरिक्त यूरिक एसिड हाइपरयुरिसीमिया को ट्रिगर कर सकता है, जिससे दर्दनाक क्रिस्टल का निर्माण हो सकता है और गुर्दे की पथरी और गाउट जैसी स्थितियां हो सकती हैं। यूरिक एसिड के स्तर को प्रबंधित करना आसान है और पोषक तत्वों से भरपूर आहार इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ड्राई फ्रूट्स केवल एक स्वादिष्ट चीज ही नहीं, वे आवश्यक विटामिन, खनिज और स्वस्थ वसा से भरपूर होते हैं जो यूरिक एसिड के स्तर को कम करने में मदद कर सकते हैं। आइए इस लेख में हम आपको ऐसे पांच ड्राई फ्रूट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो स्वाभाविक रूप से आपके शरीर के यूरिक एसिड के लेवल को कंट्रोल करेंगे।

बादाम खाएं–बादाम के सेवन से यूरिक एसिड के लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है। सकी उच्च

विटामिन ई सामग्री और कम प्यूरीन स्तर के कारण। बादाम का छिलका भी फायदेमंद होता है क्योंकि यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो मुक्त कणों से लड़ने और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद करता है। अपने आहार में बादाम को जरुर शामिल करें। यह हाइपरयुरिसीमिया के प्रबंधन और आपकी सेहत को बनाए रखने में मदद करता है।

ड्राई चेरी–हाई यूरिक एसिड के लेवल को कम करने के लिए ड्राई चेरी एक बढ़िया विकल्प है क्योंकि इनमें प्यूरीन की मात्रा कम होती है और एंथोसायनिन से भरपूर होती हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट यूरिक एसिड को कम करने और समग्र स्वास्थ्य का समर्थन करने में मदद करते हैं। सूखी चेरी में मौजूद फाइबर भी पाचन में सहायता करता है और शरीर से अतिरिक्त यूरिक एसिड को खत्म करने में मदद करता है। सूखी चेरी खाना सेहत को बढ़ावा देने और स्वस्थ यूरिक एसिड के स्तर को बनाए रखने का एक स्वादिष्ट तरीका हो सकता है।

खजूर–खजूर के सेवन से हाई यूरिक एसिड के उच्च स्तर को प्रबंधित करने में सहायता कर सकता है। इसमें आयरन, तांबा, विटामिन बी6, प्रोटीन, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इसके सेवन से सूजन से निपटने में मदद मिलती है।

पिस्ता–विटामिन ई से भरपूर, पिस्ता शक्तिशाली एंटीऑक्सिडेंट हैं जो हाई यूरिक एसिड स्तर की सूजन और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद करते हैं। यह स्वस्थ फैट्स और फाइबर पाचन स्वास्थ्य में योगदान करते हैं और हृदय समारोह का समर्थन करते हैं। अपने आहार में पिस्ता शामिल करने से यूरिक एसिड के स्तर को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करते हुए समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है।

काजू–काजू एक ड्राई फ्रूट है जो हाइपरयुरिसीमिया के खतरे को रोकने में मदद कर सकता है। काजू में कम प्यूरीन और समृद्ध पोषण के साथ, वे स्वाभाविक रूप से यूरिक एसिड के स्तर को कम करने में मदद करते हैं। काजू एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करके और एचडीएल स्तर को बढ़ाकर हृदय स्वास्थ्य में भी सहायता करता है, जिससे यह गठिया से पीड़ित लोगों के लिए एक बढ़िया विकल्प बन जाता है।

दैनिक संज्ञान दृष्टि

लखीमपुर–खीरी, शनिवार 19 अक्टूबर 2024

यूपी के मंत्री का एक और बयान, बोले प्रियंका गांधी की लाइफस्टाइल भारतीय संस्कार व संस्कृति के अनुरूप नहीं

उ0प्र0। यूपी सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह के कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पर दिए गए बयान पर एक तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ मंत्री ने एक और बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी की लाइफस्टाइल भारतीय संस्कार और संस्कृति के अनुरूप नहीं हैं। बता दें कि लखनऊ में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने मंत्री के आवास का घेराव कर नारेबाजी की और अमेठी में विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला जलाया।

मंत्री ने अपने ताजा दिए गए बयान में कहा है कि राजनीतिक सवाल पर राजनीतिक जवाब होता है। प्रियंका गांधी को चाहिए कि अपने कार्यकर्ताओं से बात करें और उन्हें अपनी बात समझाएं। मेरे लिए भारतीय संस्कार और संस्कृति से युक्त हर नारी मां भगवती के समान है, लेकिन मैं प्रियंका गांधी को भारतीय संस्कार और संस्कृति के अनुरूप नहीं पाता हूं। इसलिए किसी से सहमत और असहमत होना हमारा विचार और हमारा अधिकार है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी हार के डर से रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ रही हैं वायनाड से चुनाव लड़ रही हैं। हम लोगों की यह परंपरा है कि चुनाव की शुरुआत हर कोई अपने घर से करता है किंतु पूरे गांधी परिवार का एक भी व्यक्ति कभी भी अपने जन्मस्थान और निवास से चुनाव नहीं लड़ा। गांधी परिवार पीढ़ियों से दिल्ली के लुटियंस जोन में रहता आया है लेकिन कभी भी दिल्ली की किसी भी विधानसभा या फिर लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ा। इसका मतलब है कि आपके अपने ही घर की जनता आपको प्रेम नहीं करती है तभी आप बाहर से चुनाव लड़ते हैं। इसके पहले उन्होंने प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने को लेकर टिप्पणी की थी जिस पर कांग्रेस नेताओं ने लखनऊ स्थित उनके आवास के बाहर प्रदर्शन करते हुए मुख्य द्वार पर चोर–बेईमान लिख दिया था।

अमेठी में भी कांग्रेसियों ने किया विरोध प्रदर्शन–उधर, शुक्रवार को अमेठी में मंत्री के बयान पर युवक कांग्रेस ने गौरीगंज कस्बे के हनुमान तिराहे पर दिनेश प्रताप सिंह का पुतला फूँककर जमकर नारेबाजी की। प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने दो दिन पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को लेकर एक्स पर एक पोस्ट किया था और लिखा था कि अंततः लड़की लड़ नही पाई और भाग ही गई वहां जहां लड़ना न पड़े, बूढ़ी जो हो गई है। राज्यमंत्री द्वारा पोस्ट करते ही कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने वीडियो जारी कर दिनेश सिंह की आलोचना की। राज्यमंत्री के बयान पर कांग्रेसियों में आक्रोश व्याप्त है। शुक्रवार को युवक कांग्रेस के कार्यकताओं ने जिलाध्यक्ष शुभम सिंह के नेतृत्व गौरीगंज कस्बे के हनुमान तिराहे पर राज्यमंत्री दिनेश सिंह का पुतला फूंककर नारेबाजी की। जिलाध्यक्ष शुभम सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री दिनेश सिंह ने अमेठी की बेटी प्रियंका गांधी को लेकर अभद्र टिप्पणी की है जिससे कांग्रेसियों और अमेठी की जनता में जबरजस्त आक्रोश है। इसी को लेकर आज विरोध प्रदर्शन करते हुए दिनेश सिंह का पुतला फूंका गया है।

सीडीओ का अलग अंदाजः दरांती लेकर काटने लगे धान की फसल, किसानों से पराली न जलाने की अपील

स्पर्श सिन्हा

लखीमपुर खीरी (संज्ञान दृष्टि)। जिले में सीडीओ अभिषेक कुमार का शुक्रवार को अलग अंदाज देखने को मिला। उन्होंने किसान के साथ खेत में धान की फसल काटी। सीडीओ ने किसानों से पराली न जलाने की अपील की है।

खीरी जिले में धान की उत्पादकता जांचने के लिए टीम के साथ खेतों में पहुंचे सीडीओ अभिषेक कुमार ने शुक्रवार को किसान के साथ फसल काटी। सीडीओ का यह अंदाज देखकर लोग हैरान रह गए। इस दौरान सीडीओ ने किसान से बातचीत कर खेतीबाड़ी में आने वालीं समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली। सीडीओ अभिषेक कुमार की देखरेख में फसलों की औसत उपज और उत्पादन के आंकड़ों को जुटाने के लिए तहसील सदर की ग्राम पंचायत अगरा में धान की फसल कटाई की स्थिति का जायजा लिया गया। सीडीओ ने किसान राजेंद्र कुमार के धान के खेत में 43.3 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के 10–10–10 मीटर का समबाहु त्रिभुज का प्लॉट बनवाकर सीसीई एग्री एप के माध्यम से क्रॉप कटिंग कराई। फसल काटकर धान की तौल कराई। इस दौरान सीडीओ ने किसान के साथ मिलकर खुद भी दरांती से फसल की कटाई की। बाद में धान की तौल कराई गई। इसमें 21.44 किलोग्राम फसल प्राप्त हुई। सीडीओ ने निरीक्षण के दौरान अपर सांख्यिकीय अधिकारी हर्षित मिश्र से फसल नपाई, कटाई, जी.सी.ई.एस. एप्प पर ऑनलाइन फीडिंग आदि बिंदुओं की जानकारी ली। सीडीओ ने किसानों से फसलों का बीमा कराने और पराली न जलाने की भी अपील की है। निरीक्षण के दौरान नायब तहसीलदार सुनील कुमार, राजस्व निरीक्षक नेकी राम राना, लेखपाल कृष्ण कुमार सिंह समेत राजस्व टीम व ग्रामीण मौजूद रहे।

ईसानगर एडीओ पंचायत का रोका वेतन, मांगा स्पष्टीकरण

लखीमपुर खीरी। कलक्ट्रेट सभागार में बृहस्पतिवार को सीडीओ अभिषेक कुमार ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान की गतिविधियों की समीक्षा की।

कार्यों में लापरवाही होने और ईसानगर ब्लॉक फिसड्डी होने पर सीडीओ ने एडीओ पंचायत का वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण तलब किया। साथ ही चेतावनी दी कि अगर अब लापरवाही मिलती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सीडीओ ने डीपीआरओ, एडीओ पंचायत को ग्रामस्तर पर झाड़ी कटाई और नाली साफ सफाई के निर्देश दिए। कहा कि आशा डोर टू डोर सर्वे के दौरान आमजन को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए स्वास्थ्य कार्यक्रमों की जानकारी दें। अभियान के सभी स्टेट होल्डर विभाग माइक्रो प्लानिंग के अनुसार काम करें। सीडीओ ने स्वास्थ्य, नगर निकाय, पंचायती राज, बाल विकास एवं बेसिक, माध्यमिक शिक्षा, पशुपालन, सूचना, दिव्यांग एवं जनशक्तिकरण और उद्यान विभाग को जमीनी स्तर पर काम करने के निर्देश दिए।

राज्यपाल देवव्रत और केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी की मुलाकात में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर चर्चा

गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने अजमेर प्रवास के दौरान शुक्रवार को किशनगढ़ में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी के निवास पर पहुंचकर शिष्टाचार मुलाकात एवं चर्चा की।

इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच देश में प्राकृतिक खेती को बड़ा वादा नहीं और किसानों को उसकी तरफ आकर्षित करने के विषय पर गहन चर्चा हुई। प्राकृतिक खेती के प्रबल समर्थक राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी को प्राकृतिक कृषि पद्धति के लाभों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि यह मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारने और किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने में भी सहायक सिद्ध हो रही है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने राज्यपाल की इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और इस बात पर सहमति व्यक्त की कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सभी हरसंभव कदम उठाए जाने चाहिए।

केंद्र सरकार भी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने को लेकर लगातार प्रयासरत है और काम भी कर रही है। कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने बताया कि मोदी सरकार जीरो बजट प्राकृतिक खेती और परंपरागत कृषि विकास योजना के माध्यम से देश में प्राकृतिक खेती का माहौल बनाकर किसानों को उसे दिशा में आकर्षित करके मदद पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि धरती को रसायनों से मुक्ति दिलाने और देश के नागरिकों को शुद्ध खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिहाज से शून्य लागत में प्राकृतिक खेती एक बड़ा विकल्प बनकर उभर रही है।

गन्ना समितियों के अध्यक्षों के चुनाव में भाजपा का दबदबा

लखीमपुर खीरी। जिले की सहकारी गन्ना विकास समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर बृहस्पतिवार को चुनाव कराया गया। इसमें अरनीखाना, भीरा, जंगबहादुर गंज, खमरिया और पलिया समिति में एकल नामांकन के चलते अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है।

वहीं खीरी–पीलीभीत गन्ना विकास समिति के अध्यक्ष पद पर मतदान कराया गया। सभी जगहों पर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। लखीमपुर गन्ना विकास समिति के अध्यक्ष पद पर अखिलेश वर्मा निर्विरोध चुने गए। प्रमोद वर्मा का उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ। वहीं सहकारी गन्ना विकास समिति भीरा में अध्यक्ष पद पर राकेश सिंह और उपाध्यक्ष पद पर रमाकांत त्रिवेदी निर्विरोध निर्वाचित हुए।

अखिलेश अध्यक्ष और उमादेवी निर्विरोध बनी उपाध्यक्ष–पसगवां। सहकारी गन्ना विकास समिति जंगबहादुरगंज के संचालक मंडल के अध्यक्ष पद पर अखिलेश त्रिवेदी और उपाध्यक्ष पद पर उमादेवी निर्विरोध निर्वाचित घोषित की गईं। अखिलेश त्रिवेदी भाजपा के जिला कोषाध्यक्ष हैं। निर्वाचन अधिकारी सुभाष चन्द्रा ने बताया कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर एकल नामांकन हुआ। दोनों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया है। एसडीएम डॉ. अवनीश कुमार और निर्वाचन अधिकारी सुभाष चंद्रा ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को प्रमाण पत्र प्रदान किए। संवाद

अरनीखाना सोसाइटी के सभापति बने अशोक अवस्थी–खीरी टाउन। सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड अरनीखाना खीरी के सभापति पद पर अशोक अवस्थी का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। सत्य विजय को उपसभापति चुना गया। सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड अरनीखाना की ओर से विभिन्न सहकारी संघ एवं शुगर मिल में 12 प्रतिनिधि निर्विरोध निर्वाचित हुए। इस अवसर पर सदर विधायक योगेश वर्मा, नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ के अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू, नीरज सिंह चौहान, रोहित अवस्थी आदि मौजूद रहे।

निर्वाचित संचालकों और डेलीगेटों को नामित किया गया प्रति निधि–संचालक मंडल की अध्यक्ष बीना सिंह को इफ्को नई दिल्ली, आशुतोष कुमार, प्रवेश कुमार, गुड्डी देवी, राहुल शुक्ला, मनोज कुमार, मनदीप कुमार को गन्ना संघ लखनऊ, पारस नाथ, संगीता वर्मा, और कलेक्टर को जिला सहकारी बैंक लखीमपुर, रविंद्र कुमार और ब्रजकिशोर सरजू सहकारी चीनी मिल बेलरायां, छैल बिहारी चीनी मिल संपूर्ण नगर, अनूप कुमार वर्मा किसान सहकारी चीनी मिल अनूप शहर, आशीष कुमार और नाथूलाल किसान सहकारी चीनी मिल पुवायां, राजकुमार संखवार चीनी मिल बागपत, रईस अहमद चीनी मिल औराई, दृर्ग पाल सिंह चीनी मिल रसड़ा, आलोक कुमार को जिला सहकारी बैंक शाहजहांपुर का प्रति निधि नामित किया गया।

पहली बार महिलाओं का दबदबा–गोला गन्ना समिति में पहली बार महिला संचालकों का दबदबा है। इसमें जिला शाहजहांपुर धनसिंहपुर की बीना सिंह अध्यक्ष, लंदनपुर ग्रंट की सीमा वर्मा उपाध्यक्ष। वहीं उनके साथ ग्रंट नंबर 14 से शकुंतला देवी, फजलनगर ग्रंट से चरनजीत कौर निर्विरोध चुनकर संचालक मंडल में पहुंची हैं।

आलिया, ऐश्वर्या और न प्रियंका चोपड़ा भारत की सबसे अमीर एक्ट्रेस है 90 की ये हसीना

मुंबई। बी–टाउन स्टार्स अब ना सिर्फ फिल्मों से बल्कि कई ऐड्स, बिजनेस से करोड़पति बन गए हैं। वहीं अगर हम भारत की सबसे अमीर एक्ट्रेस की बात करें तो हो सकता है आपके दिमाग में आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण या फिर यकीनन प्रियंका चोपड़ा का नाम आएगा।

लेकिन आप गलत है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन नए नाम से नहीं बल्कि 90 के दशक की स्टारभारत की सबसे अमीर एक्ट्रेस हैं। ये जानकर भी हैरानी होगी कि साल 2009 से उनके नाम कोई बक्सि अफिस सेमी हिट फिल्म नहीं है। इसके बावजूद वो आज की टपिं स्टार्स से कहीं ज्यादा अमीर है। हम बात करें रहे हैं शाहरुख की हीरोइन जूही चावला की। जी हां, आपने ठीक सुना। वो दौर 90 के दशक का था जब इंडियन एक्टर्स ने किसी फिल्म के लिए 1 करोड़ फीस का आंकड़ा पार किया था। जल्द ही बड़े स्टार्स कई ऐड के चेहरे बन गए और पैसा पानी की तरह बहने लगा। कई एक्टर्स ने एक्टिंग के साथ–साथ बिजनेस की दुनिया में भी हाथ बढ़ाया और संपत्ति करीब 4600 करोड़ 580 मिलियन है, जो उनके किसी भी साथी कलाकार या जूनियर से कहीं अधिक है। अगर जूही के बाद पांच सबसे अमीर इंडियन एक्ट्रेस की कुल संपत्ति को एक साथ रखा जाए, तो भी ये उनकी संपत्ति से कम ही साबित होगी।

जूही के बाद दूसरे पोजिशन पर ऐश्वर्या राय बच्चन हैं, जिनकी कुल संपत्ति 100 मिलियन डॉलर लगभग 850 करोड़ से अधिक बताई गई है। प्रियंका चोपड़ा अपने ब्रांड करोड़पति बन गए। इसलिए इसमें कोई हैरानी नहीं कि भारत की सबसे अमीर एक्ट्रेस दुनिया की टपिं 10 सबसे अमीर एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल हों।

हैरानी वाली बात ये है कि जूही ने पिछले दशक में एक भी हिट फिल्म नहीं दी है। दरअसल, हुरुन रिच लिस्ट 2024 के मुताबिक, सबसे अमीर भारतीय एक्टर्स की बात करें तो उनकी संपत्ति उनके दोस्त और बिजनेस पार्टनर शाहरुख खान के बाद दूसरे नंबर पर बताई जा रही है। हुरुन के अनुसार, जूही की कुल और फिल्म प्रॉडक्शन कंपनी और हलीवुड फिल्मों की बदौलत करीब 650 करोड़ की संपत्ति के साथ तीसरे पोजिशन पर हैं।

टॉप 5 एक्ट्रेस में आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण भी हैं, जो एक्टिंग के साथ–साथ बिजन सवुमन भी बन चुकी हैं। ऐसा नहीं कि जूही चावला की सम्पत्ति का सोर्स केवल सिनेमा हो। उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा उनके बिजनेस इन्वेस्टमेंट से आता है। रेड टिलीज ग्रुप में हिस्सा के अलावा जूही क्रिकेट टीमों आईपीएल की कोलकाता नाइट राइडर्स सहित की को–प्रड्यूसर और को–ओनर हैं। बताया जाता है कि इन सबके अलावा उनके पास बहुत सारी अचल संपत्ति भी है और उनके करोड़पति व्यवसायी पति जय मेहता के साथ जॉइंट तौर पर अन्य बिजनेस में भी उनका निवेश है। जूही की आखिरी बॉक्स ऑफिस एवरेज फिल्म साल 2009 में आई फिल्म लक बाय चांस थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म का बजट 15 करोड़ था और 29 करोड़ रुपये कलेक्शन हुआ था।

बेटियों के मुंडन संस्कार के कुछ दिनों बाद रुबीना ने शेयर की अपनी खूबसूरत तस्वीरें, लाल जोड़े में बेहद हसीन दिखीं दो बच्चों की मां

मुंबई। टीवी की बसिं लेडी उर्फ एक्ट्रेस रुबीना दिलाइक सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह अक्सर फैंस के साथ अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। इसी बीच रुबीना ने अपनी बेटियों के मुंडन संस्कार से अपने खूबसूरत फोटोशूट तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की, जिन्हें खूब लाइक किया जा रहा है। इस सूट के साथ उन्होंने मैचिंग दुपट्टा कैरी किया है और हाथ में व्हाइट पोटली कैरी की हुई है। आंखों पर चश्मा लगाए, न्यूड मेकअप और खुले बालों से उन्होंने अपने लुक को कंप्लीट किया है। फैंस रुबीना की इन तस्वीरों को खूब लाइक कर रहे हैं और कमेंट कर उनके लुक की तारीफ कर रहे हैं। बता दें, रुबीना दिलाइक ने बीते साल 27 नवंबर को प्यारी सी बेटियों जीवा और एधा को जन्म दिया था। हालांकि इस खुशखबरी को एक्ट्रेस ने लगभग 1 महीने बाद यानि 27 अक्टूबर को फैंस के साथ शेयर किया था और उनके 11 महीने के पूरे होने पर उन्होंने बेटियों का मुंडन संस्कार करवाया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर सामने आई थीं।

सर सैयद डे पर गाँधी आजाद पब्लिक स्कूल की ओर से हुआ मुशायरा का आयोजन

रंजीत कुमार (संवाददाता)

आमस (संज्ञान दृष्टि)। आमस के बैदा गाँव में गाँधी आजाद पब्लिक स्कूल की ओर से मुशायरा का आयोजन किया गया.स्कूल के संस्थापक मो अली ने बताया कि सर सैयद डे के अवसर पर सर सैयद अहमद खान के जीवन में आए संघर्षो व समाज के लिए किए गए उनके कीमती कार्यों पर चर्चा की गई. उन्होंने बताया कि मुख्यअतिथि के रूप में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व कार्यकारी कुलपति डॉ तौकीर आलम फलाही व विशिष्ट अतिथि के रूप में गया कॉलेज उर्दू विभाग के डॉ अब्दुल हई खान भी शामिल हुए और द्वीप प्रज्वलित कर मुशायरा का उद्घाटन किया.सर सैयद डे के अवसर पर उपस्थित लोगों को मुख्य अतिथि ने सम्बोधित करते सर सैयद अहमद खान की जीवनी पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी. सर सैयद एक व्यक्ति का नाम नहीं है बल्कि एक मिशन, एक आंदोलन और एक काफिला का नाम है.शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता.उन्होंने सर सैयद डे के आयोजन पर खुशी व्यक्त करते हुए गाँधी आजाद पब्लिक स्कूल के चेयरमैन मुंशी नईमुद्दीन, संस्थापक मो अली, प्राचार्य जहीर अनवर और निदेशक शौकत अली आदि को बधाई दिया. विशिष्ट अतिथि ने कहा कि उर्दू जुबान व अदब पर सर सैयद का बहुत बड़ा एहसान है.इसके बाद मुशायरा आरम्भ हुआ जिसकी अध्यक्ष अहमद असलम और संचालन इमरान अली ने किया।

इस अवसर पर जिन शायरों ने अपना बेहतरीन कलाम पेश किया उनमें अहमद असलम, इशराक हमजापूरी, नसीमुद्दीन बैदावी, इमरान अली, जमशेद अशरफ, मो जहांगीर आलम अहसन गयावी और सरवर गयावी शामिल हैं. अंत में स्कूल के एचएम जहीर अनवर ने धन्यवाद ज्ञापन किया. इस अवसर पर आमस प्रमुख लड्डन खान,राजद नेता जसीमुद्दीन, वसीम अकरम,कमाल हारिस, इम्तेयाज आलम, मुनीब अली, मूर्तजा अली, आबिद ईमाम, अबू अरीबा, इमरोज अली जीशान खान, मुंशी नईमुद्दीन, मोजीबुर्रमान, डॉ अफजल हुसैन, हिफजूर रहमान रिंकू, शहबाज आलम, राशिदुल हक, नदीम अख्तर, हातिम फिरोज,तौकीर आलम, यासीन खान, मुहैब अकरम, डॉ मोख्तार अहमद, मोईन उद्दीन हैदर, अयाज खान, मोनाजिर हुसैन, जमील अख्तर, शाहिद अली, मो बेलाल मोजफ्फर हुसैन, जब्बार अहमद, अतीकुर रहमान, मो मुजतबा,मो सुलेमान, जावेद हैदर, सफदर अली, जमशेद हमजापूरी,शाहिद, अली, नन्हे खान, शमशीर आलम तबरेज आलम, अतिब रजा, आलम शैख, शाहिद अंसारी, महमूद आलम आदि सैकड़ों लोग उपस्थित थे.

एक नज़र

सिद्धार्थनगर– हेमंत जायसवाल और नसीम खान का खेल खुला, उसका बाजार के वार्ड नंबर 4 में सिंडिकेट बनाकर खेल, हेमंत ने नगर पंचायत चेयरमैन रहते 83 लाख हड़पा, तालाब सुंदरीकरण का टेंडर आजाद इंटरप्राइजेज को मिला था, आजाद इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर नसीम की मिलीभगत, हेमंत के साथ मिलकर 83 लाख रुपए की बंदरबांट की, तालाब सुंदरीकरण के लिए 1.66 करोड़ मंजूर हुआ था, बिना काम कराए ही 83 लाख रुपए निकाल लिया गया, मौके पर आजाद इंटरप्राइजेज, नसीम ने काम नहीं कराया, सीढ़ी, बेंच, चबूतरा, गेट आदि का निर्माण किया जाना था, वार्ड नंबर 4 कृष्णा नगर में तालाब की सफाई तक नहीं, बिना काम कराए ही हेमंत और नसीम ने पैसा हड़प लिया।

रायबरेली– युवक ने किया असलहे और कारतूस का प्रदर्शन, असलहे के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस जांच में जुटी, महराजगंज क्षेत्र के रहने वाले बताये जा रहे युवक।

पीलीभीत– मशान घाट में बने मंदिर में कुल्हाड़ी से काटकर हत्या, भाभी से अवैध संबंध को लेकर भाई ने की बेरहमी से हत्या, हत्या कर आरोपी भाई मौके से हुआ फरार,पुलिस जांच में जुटी, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, पत्नी से अवैध संबंधों को लेकर विवाद के बाद भाई की हत्या, पीलीभीत थाना न्यूरिया इलाके के बहरुवा गांव की घटना।

पीलीभीत– मैन पॉवर के टेंडर को लेकर मेडिकल कॉलेज में खेल, पिछले 1 साल से नहीं हो पा रहा मैन पॉवर का टेंडर, प्रिंसिपल डॉक्टर संगीता अनेजा नहीं होने दे रहीं टेंडर, अगस्त 2024 में निकला टेंडर अभी तक फाइनल नहीं, संगीता अनेजा ने क्वालीफाई कंपनी को टेंडर नहीं दिया, अपनी खास कंपनी को टेंडर देना चाहती हैं डॉक्टर संगीता, जिस कंपनी के सभी मानक पूरे उसका टेंडर अस्वीकृत किया, पति डॉ जीके अनेजा पीलीभीत में टेंडर की डीलिंग करते हैं, संगीता पर भ्रष्टाचार के लगे थे आरोप,हुई थी लोकायुक्त जांच।

बुलंदशहर– राशन डीलर के खिलाफ तहसील में धरने पर बैठे ग्रामीण, ग्रामीणों ने राशन डीलर पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, ग्रामीणों का आरोप राशन डीलर हक पर डाल रहा डाका, डीलर राशन देने के दौरान ग्रामीणों से करता है अभद्रता, ग्रामीण पहले भी कई बार कर चुके अधिकारियों से शिकायत, राशन डीलर को हटाने की मांग पर अड़े कई दर्जन ग्रामीण, पहासू ब्लॉक क्षेत्र के गांव बिकूपुर रामनगर का मामला।

यदि आप संज्ञान दृष्टि पर कोई विज्ञापन देना चाहते है या किसी अन्य प्रकार के व्यावसायिक अनुबंध के इच्छुक है तो हमे
sangyandristinewspaper@gmail.com
पर ईमेल कर सकते हैं।
व्हाटसएप नम्बर
+91–7080049049

व्हाट्सएप पर सम्पर्क के लिए
70800–49049
95824–49049
Website :
www.sangyannews.com
sangyandrsitinewspaper@gmail.com

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक प्रांजल श्रीवास्तव द्वारा मंजुला आफसेट, काशीनगर, लखीमपुर–खीरी से मुद्रित तथा 132/2 काशीनगर चोपड़ा इंडस्ट्री लखीमपुर–खीरी, उ0प्र0 से प्रकाशित

सम्पादक– प्रांजल श्रीवास्तव

(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी)

ऐरा चीनी मिल के तीसरी बार डायरेक्टर चुने गए राम नरेश मिश्रा

गन्ना विकास समिति ऐरा के अध्यक्ष बने राजू सिंह ,उपाध्यक्ष विजय प्रताप सिंह निर्विरोध निर्वाचित!

धर्मेश शुक्ला

लखीमपुर–खीरी (संज्ञान दृष्टि)। तहसील धौरहरा क्षेत्र की गन्ना विकास समिति ऐरा में गुरुवार को पुलिस सुरक्षा के बीच तीसरी बार राम नरेश मिश्रा डायरेक्टर के पद पर नामित किया गया। क्षेत्रीय लोगों ने उन्हें मिठाई व माला फूल पहनाकर शुभकामनाएं दिया हैं धौरहरा विधायक विनोद शंकर अवस्थी ने कहा कि राम नरेश मिश्रा सेमरी निवासी बहुत ही निष्ठावान पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और धौरहरा के गांव सेमरी से आकर जिले की राजनीति करना अपने आप में प्रमाण है अपनी कुशल कार्यशैली व मेहनतकश स्वभाव के चलते राम नरेश मिश्रा तीसरी बार डायरेक्टर चुने गए।

धौरहरा विधायक विनोद शंकर अवस्थी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज का यही संकल्प है की प्रत्येक कार्यकर्ता सक्षम बने जो निष्ठावान कार्यकर्ता है उनको सरकार बराबर सम्मान देने का काम कर रही है तथा उत्तर प्रदेश के अंदर 7 वर्षों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपना कर सरकार से ग्राम प्रधान तक सब लोकहित में कार्य कर रहे हैं इसी का नतीजा है कि आज राम नरेश मिश्रा को उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना विकास समिति में तीसरी बार डायरेक्टर पद पर सरकार द्वारा नामित किया गया है।

वही अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। डायरेक्टर पद पर चुने गए मूडी निवासी राजू सिंह पुत्र रमेश सिंह ने अध्यक्ष पद के लिए व उपाध्यक्ष पद के लिए हरदासपुर निवासी विजय प्रताप पुत्र तेज प्रताप सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किया। निर्धारित समयावधि तक कोई अन्य नामांकन पत्र नहीं खरीदा गया। जिसके चलते दोपहर आर ओ शैलेंद्र कुमार ने ऐरा गन्ना विकास समिति के अध्यक्ष पद पर राजू सिंह व उपाध्यक्ष पद पर विजय प्रताप सिंह को निर्विरोध निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उपस्थित डायरेक्टर उत्तरा सिंह, भानु प्रताप सिंह,कमल किशोर सिंह, होशियार बक्श सिंह, सरयू प्रकाश पांडे, संतोष कुमारी, अमरीश भार्गव, शत्रोहन लाल राजपूत, राजकिशोर चौधरी के साथ समर्थक रमेश सिंह, ज्ञानेंद्र वर्मा, अभय प्रताप सिंह, संतोष मिश्रा, राजकुबेर सिंह, खिलाड़ी सिंह, कमलेश भार्गव, गुड्डू सिंह, लाल बहादुर सिंह मौजूद रहे।

झारखंड सरकार वकीलों को पेंशन देगी, ऐसा करने वाला पहला राज्य

संज्ञान दृष्टि टीम

झारखंड (संज्ञान दृष्टि)। झारखंड सरकार 65 वर्ष से अधिक उम्र के वकीलों को हर महीने 7 हजार रुपए पेंशन देगी। लाइसेंस सरेंडर करने वाले ऐसे वकीलों को अब तक अधिवक्ता कल्याण कोष से 7 हजार रुपए मिलते थे। अब राज्य सरकार भी 7 हजार रुपए देगी। यानी इन्हें वकीलों को अब 14 हजार रुपए प्रति माह मिलेंगे। झारखंड कैबिनेट ने शुक्रवार को वकीलों के फायदे वाले दो और फैसले किए। सरकार अब नए वकीलों को स्टाइपेंड के रूप में पहले तीन साल तक हर महीने ढाई हजार रुपए देगी।

मेरा प्रखंड मेरा गौरव'' प्रतियोगिता के तहत का आयोजन से अनदेखे पर्यटन स्थलों को मिलेगा पहचान

रंजीत कुमार (संवाददाता)

गया (संज्ञान दृष्टि)। पर्यटन विभाग, बिहार तथा जिला प्रशासन, गया के संयुक्त तत्वावधान में ''मेरा प्रखंड मेरा गौरव'' नामक एक विशेष प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य उन पर्यटन स्थलों को पहचान दिलाना है, जो अब तक आम लोगों और पर्यटकों की नजरों से दूर रहे हैं। इस पहल के तहत स्थानीय लोगों की मदद से इन अनदेखे स्थलों को राज्य के पर्यटन मानचित्र पर लाया जाएगा, जिससे न केवल इन स्थलों का विकास होगा बल्कि इन क्षेत्रों में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

यह प्रतियोगिता पूरी तरह ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता में हर प्रखंड से प्रतिभागी अपने प्रखंड के किसी ऐसे स्थल की पहचान करेंगे, जो अब तक अनदेखा या उपेक्षित रहा हो, लेकिन पर्यटन की दृष्टि से उसका विशेष महत्व हो। चयनित स्थल का फोटो और वीडियो प्रतिभागियों को अपलोड करना अनिवार्य होगा। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि फोटो और वीडियो की गुणवत्ता उच्च हो, ताकि स्थल की विशेषताएं स्पष्ट रूप से सामने आ सकें। इसके अलावा, स्थल का ऐतिहासिक या धार्मिक महत्व 200 शब्दों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। इसमें उस स्थल से जुड़ी कहानी, ऐतिहासिक घटना या धार्मिक महत्व को विस्तार से बताया जाना चाहिए। वीडियो में स्थल को प्रमुखता से दिखाया गया हो और उसके महत्व को समझाने का प्रयास किया गया हो।

महत्वपूर्ण शर्त यह है कि वीडियो प्रतियोगिता की अवधि के दौरान ही शूट किया गया होना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो कि प्रतिभागी ने स्थल का ताजा विवरण प्रस्तुत किया है। प्रतियोगिता में भाग लेने की अंतिम तिथि 1 नवंबर 2024 है। इसके बाद अपलोड की गई प्रविष्टियों में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। प्रतियोगिता में चार प्रमुख श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे: जुरी अवार्ड, पीपुल्स च्वाइस अवार्ड, सांत्वना पुरस्कार और अन्य श्रेणियों के पुरस्कार। प्रत्येक प्रखंड से एक ऐसे स्थल का चयन किया जाएगा, जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, और उसका विवरण विभाग को अग्रसारित किया जाएगा।

प्रभारी पदाधिकारी, पर्यटन शाखा, गया ने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक प्रतिभागी पर्यटन विभाग के आधिकारिक वेबसाइट, tourism-bihar-gov-in पर जाकर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के बाद प्रतियोगिता के चयनित स्थल का विवरण फोटो और वीडियो सहित अपलोड करना होगा। एक बार प्रविष्टि करने के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, एक प्रतिभागी केवल एक प्रखंड से एक ही स्थल के लिए प्रविष्टि कर सकता है। प्रतिभागी अपने स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी से इस प्रतियोगिता की जानकारी और सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने और अनदेखे स्थलों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की एक सराहनीय पहल है, जो बिहार के पर्यटन उद्योग में एक नया अध्याय जोड़ने का प्रयास करेगी।

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर भड़के राजद प्रवक्ता श्रवण उर्फ बंटू सिंह

रंजीत कुमार (संवाददाता)

बिहार (संज्ञान दृष्टि)। बिहार के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बिहार के भागलपुर से किसनगंज तक भ्रमण पर हैं। जिसमे उनके द्वारा दिये गए बयान पर राजद प्रदेश प्रवक्ता श्रवण सिंह उर्फ बंटू सिंह भड़क उठे हैं, और गिरिराज सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए बोले, की मंत्री गिरिराज सिंह जी जिस तरह के कार्य कर रहे हैं, और बयान दे रहे हैं, वो समाज को विभाजित करेगा, उन्हें इन सब बयानों से बचना चाहिए। यह चुनाव से पहले हिन्दू मुसलमान करने के फिराक में हैं, ताकि बहुसंख्यक हिन्दू वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके।

जबकि सरकार और भाजपा को समाज को विकसित करने के लिए कार्य करना चाहिए, लेकिन उसके बजाय भाजपा व उनके मंत्री लगातार समाज को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए यूपी सरकार को भी आड़े हाथ लेते हुए बताया, की अगर भाजपा व उनके मंत्री इतने ही सच्चे और अच्छे हैं, फिर उत्तर प्रदेश में क्यों कत्लखानों में गायों को मारा जाता है, भाजपा सरकार को सबसे पहले देश मे चल रहे कत्लखानों का लाइसेंस रद कर गौहत्या को बंद करवाना चाहिए, ये उनके हाथ मे है, लेकिन ये करने के बजाय ये लोग सड़कों पर गौरक्षा के नाम पर लोगो को सिर्फ भड़काने और गुमराह करने का काम करते हैं।

देर रात चेकिंग के दौरान 2 चाकूधारी गिरफ्तार

विशाल अग्रवाल

उधम सिंह नगर/केलाखेड़ा (संज्ञान दृष्टि)। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर द्वारा जनपद में संदिग्ध व्यक्ति,वस्तु एवं अवैध शस्त्रों की बरामदगी के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के तहत थानाध्यक्ष अशोक कुमार के मार्गदर्शन में पुलिस द्वारा रात्रि में संदिग्ध व्यक्तियो की चौकिंग के दौरान रात्रि में केलाखेड़ा स्वार सडक पर ढिल्लन धर्म कांटे के पास से अभियुक्त रमेश सिंह निवासी ग्राम रम्पुराकाजी उम्र 30 वर्ष एवं दूसरा अभियुक्त लाला सिंह उम्र 25 वर्ष के कब्जे से एकदृएक अदद चाकू बरामद किया गया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया तथा दोनों के खिलाफ आर्मएक्ट के अभियोग पंजीकृत कर न्यायलय के समक्ष पेश किया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम मे अपर उपनिरीक्षक मोहित कुमार कांस्टेबल इमदाद हुसैन, गोविन्द सामंत और मुकेश बोहरा प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

आगरा गल्ला व्यवसायी की दबंगई

आगरा– गल्ला व्यवसायी ने दिखाई दबंगई, सरे बाजार सप्लाई इंस्पेक्टर से की मारपीट, पूर्ति निरीक्षक को बस के आगे धकेलने का प्रयास, दुकान पर सरकारी चावल की सूचना पर गए थे, बौखलाए दबंग व्यवसायी निरीक्षक ने कर दी मारपीट, मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया, आगरा के खेरागढ़ कस्बे का मामला।

घरों से ढाई लाख से अधिक का माल ले उड़े चोर

घनश्याम गुप्ता (पत्रकार)

रायबरेली हलोर (संज्ञान दृष्टि)। चोरी रुकने का नाम नहीं ले रही है चोरों से परेशान जनता! प्रशासन के इतने प्रयासों के बाद भी चोरों का हौसला बुलंद! जमुरावा गांव निवासी कल्लू ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि वह निमंत्रण में शामिल होने के लिए पत्नी समेत मुंशीगंज गया था! घर में केवल उसकी बहू और दो छोटे–छोटे बच्चे थे !रात में चोर दीवार फांदकर के घर में घुसे जेवरात सहित 5000 की नगदी लेकर फरार हो गए भुक्त भोगी भोगी ने बताया कि जेवरात व नकदी मिलकर डेढ़ लाख का सामान चोर चुरा ले गए हैं!

आवाज होने पर बहू ने शोर मचाया तो चोर भाग गए कोतवाल जगदीश यादव ने बताया कि तहरीर मिली है जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी!

उधर लालगंज कोतवाली क्षेत्र के शेखवापुर गांव में लाला लोधी के घर से 80,000 के जेवर और नगदी चोरों ने पार कर दी! घर के पिछवाड़े खाली पड़ी जमीन पर सीढ़ी लगाकर घर में घुसे पुलिस का कहना है की जांच के बाद केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी!

दुचाकी चोरटा पोलिसांच्या जाळ्यात

सय्यद मुदस्सीर

यवतमाळ (संज्ञान दृष्टी)। यवतमाळ आर्णी : एका अट्टल दुचाकी चोरट्याला पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या. तसेच त्याच्याकडून चोरीतील चार दुचाकींसह एकूण पावणे दोन लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. ही कारवाई शहर पोलिसांनी गुरुवार, १७ ऑक्टोबरला दुपारी करण्यात आली.

आकाश चव्हाण रा. बजरंग चौक, जवळा असे चोरट्याचे नाव आहे. शहरात एका पाठोपाठ एक अशा दुचाकी चोरीच्या घटना घडत होत्या. १७ ऑक्टोबरला दुपारी चोरटा आकाशने दुचाकी चोरीच्या काही घटनांना मूर्तरूप दिले असून तो आर्णी शहरात आला असल्याची गोपनीय माहिती ठाणेदार सतिश चवरे यांना मिळाली होती. शिवाय एका दुचाकीची चोरी करतांना सिसिटिव्ही फुटेजमध्ये आढळून आला होता. त्यावरून चोरटा आकाश याला ताब्यात घेण्यात आले. पोलिसांनी त्याची कसून चौकशी

केली. तेव्हा त्याने दुचाकी चोरीच्या चार घटनांची कबूली दिली. शिवाय त्याच्याकडून चोरीतील दुचाकीही जप्त करण्यात आल्या. काही दुचाकीचे स्पेअर पार्ट खोलून जवळा येथील ग्रामपंचायत कॉम्प्लेक्स मधील बीएसएनएल ऑफिसमध्ये गाडीचे पार्ट ठेवण्यात आले होते.या कारवाईत पोलीस उपनिरिक्षक गजानन राजमलू, जमादार रवी नेवारे, सुनील पैठणे, अंकुश फेंडर, राजकुमार कांबळे, सागर पथ्थे, आर्णी पोलीस ठाण्यातील सहायक पोलीस निरीक्षक देशमुख, जवळा बीट अरुण चव्हाण, कर्मचारी ऋषीकेश इंगळे, नितीन वास्टर, अरविंद चिमटे आदिंनी सहभाग घेतला होता.

शेतकऱ्यांची दिवाळी अडचणीत

सय्यद मुदस्सीर

यवतमाळ (संज्ञान दृष्टी)। यवतमाळ महागाव. दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात सोयाबीनची काही मोठ्या प्रमाणात आवक वाढली आहे. पण इतर धान्याची विशेष आवक नाहीत, हे मात्र तितकेच खरे.यंदा निसर्गाच्या लहरीपणामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी चांगलाच मेटाकुटीला आला आहे, शेतकऱ्यांनी मागील वर्षीच्या उत्पादनातून शिल्लक राहिलेले काही धान्य, कडधान्य साठवून ठेवले होते. पण निसर्गाच्या अनियमितपणामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शेतीच्या लागवड खर्चासाठी घरी साठवून ठेवलेले उत्पादन मिळेल त्या भावात विकावे लागले. यामुळे आता दिवाळी सण तोंडावर आलेला आहे. आता शेतकऱ्यांना नव्या सोयाबीनवरच अवलंबून राहावे लागत आहे. यंदा ऑक्टोबर महिना अर्धा उलटून गेला तरी वरुणराजा शांत व्हायचे नाव घेत नसल्याने सोयाबीन उत्पादकांना सोयाबीनचे उत्पादन घरी आणण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. हल्ली जवळपास सर्वच शेतकऱ्यांचे सोयाबीन सवंगणीला आले आहेत. तर ज्यांचे सोयाबीन मळणीला आले आहे त्यांना वरुणराजा सतावत आहे. शेतकरी ही सोयाबीन विकून दिवाळी साजरी करण्याच्या तयारीत आहेत पण, चांगला भाव मिळाला तरच शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड होणार आहे.आता दिवाळी साजरी कशी करावी, हा प्रश्न शेतकऱ्यांना भेडसावत आहे. जिल्ह्यातील ३० ते ४० टक्के शेतकऱ्यांचे सोयाबीन घरी आले खरे पण सततच्या पावसाने तेही काळवंडले व बारीक झाले आहे. यामुळे उताराही चांगलाच घटला असून हल्ली प्रति एकर २ ते ३ क्विंटलचा उतारा मिळत असल्याचे शेतकरी सांगतात.

शेतकऱ्यांची दिवाळी अडचणीत ,यावर्षी अतिप्रमाणात पडलेल्या पावसामुळे खरिपातील उभ्या पिकांची पुरती वाट लागली. यातून बचावलेले पीक वाचवण्यासाठी कर्ज काढून खर्च केला.

एकतर शेतकऱ्यांच्या माला भावाला सुद्धा भाव नाही आहे, त्यामुळे आता दिवाळी साजरी कशी करावी, ही मोठी समस्या निर्माण झाली आहे.'' प्रतीक पाटील नरवाडे सामाजिक कार्यकर्ता महागाव